मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की मांग: हिंसा बंद करो, जीने का हक दो

■ संवाददाता

मुंबई : 'हिंसा बंद करो' हिंसा चाहे जैसी भी हो चाहे वह सांप्रदायिक हो, बम का आतंक हो या भीड़ की दहशत गर्दी हो इसे बंद किया जाय, यह मांग है 'मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी' (एमएसडी) नामक संस्था की. कल इंडियन मर्चेंट चेंबर में एक संवाददाता सम्मेलन लेकर उक्त संस्था ने यह मांग उठायी है.

पिछले दिनों अंधेरी में मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया जिसमें मुख्य मुद्दा था हिंसा बंद करो, समान नागरी संहिता पर सरकार अपना एजेंडा जाहिर करे तथा नियम-कानून को सही किया जाय. इसके अलावा भी कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया.

मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के प्रवक्ता जावेद आनंद ने 'महानगर' को बताया कि हम लोगों ने मुख्य रूप से हिंसा रोकने, नियम-कानून और समान नागरी संहिता के अलावा हज की सब्सीडी पर भी मांग की है. उन्होंने कहा कि देश में होने वाली हिंसा वह

(शेष पृष्ठ १२ पर)

मुस्लिम *(पृष्ठ १से)* H.M. (12) 3/10/2007

चाहे जैसी भी हो उसे रोकना चाहिए इसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों की जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में होने वाली हिंसा या आतंक पर काबू करना चाहिए.

इसके अलावा गुजरात के दंगों के तमाम केस गुजरात से बाहर की अदालत में चलाने की भी मांग की गयी जावेद आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हम स्वागत करते हैं, जो उसने मानवाधिकार आयोग की याचिका पर गुजरात दंगों के मामले में दिया है.

समान नागरी संहिता के बारे में जावेद आनंद ने बताया कि जब भी चुनाव का समय करीब आता है संघ परिवार के लोग इसे लागू करने की गुहार लगाने लगते हैं. लेकिन अब किसी को यह पता नहीं है कि समान नागरी संहिता का एजेंडा क्या है, किस प्रकार का कानून सरकार लागू करना चाहती है. समान नागरी संहिता के बारे में अपने एजेंडे को सरकार चुनाव के पहले जारी करे और फिर उस पर एक बहस के बाद ही उसे लागू किया जाय. जावेद आनंद ने कहा कि इन मुद्दों के अलावा हज पर दी जाने वाली सब्सीडी का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया और इस पर सरकार से मांग की गयी कि सब्सीडी बंद की जाय सिर्फ फंसाने वाली बात है इसका पूरा फायदा एयर इंडिया को होता है जबकि एयर इंडिया के अलावा दूसरी उड़ानों में किराया काफी सस्ता है फिर हाजी एयर इंडिया से क्यों सफर करें और सरकार उन पर सब्सीडी का एहसान लादे. एमएसडी द्वारा एक प्रस्ताव पास कर उसमें सभी उपरोक्त मांगें रखीं गयीं, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुसार सबको हक दिया जाय. संविधान की धारा २१ के अनुसार लोगों को जीवनयापन की आजादी दी जाय.